

3 हजार 7 सौ करोड़रु. की लागत से 9 5 एकड़ में बनेंगे राजस्थान मण्डपम् और जी.सी.सी.

राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में आर्थिक विकास को गति देने के लिए दो नई भूमि आवंटन नीतियों को मंजूरी

जयपुर, 23 अगस्ता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में प्रदेश की आर्थिक समृद्धि, सतत् विकास एवं समावेशी प्रगति के विजन डॉक्यूमेंट ‘विकसित राजस्थान/2047’ एवं 2 नीतियों को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही, आगामी विधानसभा सत्र को देखते हुए 3 विधेयों के प्रारूप के अनुमोदन, परवन बांध डूब क्षेत्र के विस्थापितों की विशेष अनुग्रह राशि स्वीकृत करने तथा युवाओं में उद्यमता को प्रोत्साहन देने से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले किए गए।

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल,

लक्ष्य रखा गया है।

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा युवाओं को स्वावलंबी बनाने एवं रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करने के उद्देश्य से विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना को मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि राज्य में सार्वजनिक, सामाजिक, धार्मिक एवं चैरिटेबल संस्थाओं, ट्रस्ट, निजी निवेशकों, कम्पनियों तथा विभिन्न विभागों द्वारा शैक्षणिक, चिकित्सकीय, औद्योगिक, व्यावसायिक और पर्यटन इकाइयों आदि के लिए भूमि आवंटन



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

■ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने “विकसित राजस्थान/2047” विज़न डॉक्यूमेंट का अनुमोदन किया। इसमें 2030 तक राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर तथा 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

■ मंत्रिमंडल बैठक में एयरो स्पेस्टर्स गतिविधियों के लिए हवाई पट्टियां लीज़ आवंटन नीति को भी मंजूरी दी गई।

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ तथा जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने परस्पर वार्ता में बताया कि भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप राज्य सरकार के ‘विकसित राजस्थान/2047’ विजन डॉक्यूमेंट का मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदन किया गया।

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि इस विजन डॉक्यूमेंट में राजस्थान को वर्ष 2030 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और वर्ष 2047 तक 4.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का

प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी, एकरूप बनाने के उद्देश्य से “नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति-2025” लाई जा रही है।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि राज्य में एयरो स्पेस्टर्स गतिविधियों को बढ़ावा देने, वर्तमान में कम उपयोग में आ रही हवाई पट्टियों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने और एडवेंचर ट्यूरिज्म को प्रोत्साहन देने के लिए एयरो स्पेस्टर्स गतिविधियों हेतु हवाई पट्टियों की भूमि लीज आवंटन नीति को मंजूरी दी गई है। इस नीति से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने बताया

कि बी-2 बाईपास, जयपुर स्थित रीको की 95 एकड़ भूमि पर राजस्थान मण्डपम्, ग्लोबल कैथेबिलिटी सेंटर, आईटी टावर का निर्माण राज्यस्त्रुजन सह विकास मॉडल के आधार पर एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के माध्यम से कराये जाने के प्रस्ताव का कैबिनेट द्वारा अनुमोदन किया गया। इस भूमि पर राजस्थान मण्डपम्, ग्लोबल कैथेबिलिटी सेंटर/आईटी टावर, 5-स्टार होटल, 4-स्टार होटल, आवासीय एवं वाणिज्यिक टावरों का विकास किया

जाएगा। परियोजना की कुल अनुमानित लागत लगभग 3700 करोड़ रुपए है, जिसमें 635 करोड़ रुपये की भरपाई राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। परियोजना पूर्ण होने की अनुमानित अवधि 30 माह है। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। संसदीय कार्य मंत्री पटेल ने बताया कि राज्य सरकार वन स्टेट, वन इलेक्शन को लागू करने की दिशा में निरंतर जरूरी कदम उठा रही है।

इलैक्ट्रॉनिक फार्मास्युटिकल व सोलर एनर्जी के सामान...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) है। दोनों देश अमेरिका डॉलर पर निर्भरता कम करने, स्थानीय मुद्राओं में लेन-देन बढ़ाने और ग्लोबल साइज के संधियों को मजबूत करने वाले कदमों का समर्थन करते हैं। ब्रिक्स की पहल “न्यू डेवलपमेंट बैंक” को भारत का समर्थन प्राप्त है, भले ही उस पर बीजिंग का प्रभाव अधिक हो।

ऊर्जा क्षेत्र इस मेलजोल को और गहरा करता है। भारत की रूस से रियायती कच्चे तेल की बढ़ती खरीद, जो अक्सर रुपये, दरिद्रता या युआन में तय की जाती है, डॉलर-विहीन वित्तीय व्यवस्थाओं की दिशा में चीन की सोच के अनुरूप है। दिल्ली इसे व्यावहारिकता के रूप में देखता है जैसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए सस्ती ऊर्जा सुनिश्चित करना, लेकिन इसका समग्र प्रभाव यह होता है कि यह डॉलर वरचस्व को चुनौती देने में चीन के साथ खड़ा दिखता है। वहीं, अमेरिका की आर्थिक नीति ने स्थिति को जटिल बना दिया है।

भारतीय स्टील, रसायनों और दवाइयों पर लागू गए शुल्क भारत के निर्यात के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। हाल ही में, अमेरिका की ओर से रूस से कच्चे तेल की खरीद पर उपर्ज चेतानियों ने दिल्ली में असंतोष व्यक्त किया है, जो कहता है कि उसकी ऊर्जा सुरक्षा को पश्चिमी प्रतिबंधों के अधीन नहीं किया जा सकता।

ये कदम भारतीय नीति निर्माताओं में यह धारणा मजबूत करते हैं कि अमेरिका एक भरोसेमंद राजनीतिक साझेदार हो सकता है, लेकिन एक आर्थिक साझेदार के रूप में वह अविश्वसनीय है। इसके विपरीत, ब्रिक्स के भीतर चीन की बढ़ती-जैसे स्थानीय मुद्रा व्यापार और वैकल्पिक भुगतान

प्रणाली-भारत को अधिक स्वतंत्रता देती है।

रूस की भूमिका इस संतुलन गतिविधि को और तीव्र करती है। दशकों से, मांस्को भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद से, वह एक प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता भी बन गया है। रूस की चीन पर बढ़ते निर्भरता के कारण भारत की मास्को से नजदीकियाँ अनिवार्य रूप भारत को से बीजिंग के करीब ले आती हैं।

ब्रिक्स जैसे मंचों पर यह त्रिकोणीय संबंध स्पष्ट हो जाता है। रूस और चीन पश्चिमी वर्चस्व को चुनौती देने में एकजुट

हैं, जबकि भारत-चीन से सतर्क रहते हुए भी-आईएमएफ सुधार या डॉलरीकरण-विरोध जैसे मुद्दों पर रूस व चीन के साथ खड़ा होने में सामरिक लाभ देखा है। दिल्ली और बीजिंग में भरोसे का नहीं बल्कि सुविधा नहीं, बल्कि सुविधा जोड़ती है। भारत की यह प्रतीत होती विरोधाभासी नीति-राजनीतिक रूप से अमेरिका से मेल और आर्थिक रूप से चीन से सहयोग-उसकी दीर्घकालिक "रणनीतिक स्वायत्तता" की नीति का ही प्रतिबिंब है। शीत युद्ध के समय से ही भारत ने किसी भी ध्रुवीय गुटबंदी से दूर रहते हुए प्रतियर्षी शक्तियों के बीच

संतुलन बनाए रखने की नीति अपनाई है।

यह संतुलन एक सोची-समझी रणनीति है। सुरक्षा के मोर्चे पर अमेरिका से मेल रखते हुए और वित्तीय स्तर पर चीन के साथ सहयोग करते हुए भारत दोनों से लाभ उठाता है। यह अमेरिका को संकेत देता है कि यदि वह दंडात्मक व्यापार उपाय अपनाएगा, तो भारत चीन के करीब जा सकता है, वहीं यह चीन को बताता है कि अमेरिका के साथ सुरक्षा सहयोग पर कोई समझौता नहीं होगा।

अमेरिका के लिए, ब्रिक्स में भारत की भागीदारी जो डॉलर की प्रधानता को चुनौती देती है, में भारत की भागीदारी

यूरोपीय देश एकजुट होकर अमेरिका ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) पुतिन ने बहुत स्पष्ट रूप से रूस के लिए अपने विजय को व्यक्त किया जो वह अतीत के साम्राज्यों की रोशनी में देख रहे हैं।

इसी के समानांतर, रूस ने, जैसा कि उम्मीद थी, अमेरिका की उस पहल को तुकरा दिया जिसमें अमेरिका की अगुवाई में रूस और यूक्रेन के नेताओं की निपक्षीय बैठक का प्रस्ताव था। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी ने ऐसा संकेत दिया है।

रूस की स्थिति को विसंगति साफ झलकती है क्योंकि वह एक दुविधा में फंसा हुआ है और कुछ देशों को छोड़कर, यूक्रेन को अधीन करने की कोशिश में रूस पूरी तरह अलग-थलग खड़ा है।

रूसी विदेश मंत्री के बयानों से संकेत मिलता है कि शांति समझौते की बातचीत की संभावनाएँ हो सकती हैं। रूसी नेता, जो एक माहिर राजनयिक और विदेश नीति के जानकार हैं, ने संकेत दिए

हैं कि वार्ताएँ फिर से शुरू हो सकती हैं। लावरोव ने संकेत दिया कि यूक्रेन ने अब तक उन वार्ता शर्तों को स्वीकार नहीं किया है जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रस्तावित की थीं, यानी क्षेत्रीय समझौता और यूक्रेन का नाटो में शामिल न होना। उन्होंने कहा कि यूक्रेन ने इन शर्तों को नहीं माना है।

उन्होंने आगे कहा कि पुतिन शांति वार्ता तभी करेंगे जब शांति की शर्तों का विवरण स्पष्ट हो। यह रूसी भाषा में फिलहाल सीधे वार्ता न करने का संकेत है।

फिर भी, रूस अब उस व्यापक गठबंधन से अलग है जो यूरोप और मध्य अटलांटिक दोनों और उसके खिलाफ खड़ा है। अमेरिका लगातार शांति समझौते को पूरा करने के लिए उत्सुक रहा है। उसने यूरोपीय देशों और यूक्रेन को ज़मीनी के अदला-बदली वाले समझौते की शर्त स्वीकार करने के लिए मनाने की कोशिश की।

पहले, यूरोपीय देश और यूक्रेन रूस को क्षेत्रों को सौंपने पर किसी समझौते पर नहीं पहुँच सके। वास्तव में, यूक्रेन तो रूस से क्रीमिया को वापस लेने की कोशिश में लगा हुआ था और उसकी सैन्य शक्ति का बड़ा हिस्सा क्रीमिया के संबंधों को पूरी तरह तोड़ने पर केंद्रित था।

खराब लड्डू ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) की। उसने जब खुद प्रसाद ग्रहण किया तो पता चला कि लड्डूओं में से बंदवू आ रही थी। इस पर उसने अपने परिचित कैलाश से घी की जांच करने के लिए कहा तो पता चला कि घी खराब था। जिस पर परिवर्दी ने तुरंत ही विपक्षी हलवाई को खराब लड्डू बेचने की शिकायत की। विपक्षी ने उसे कहा कि वे प्रसादी लौटा दें और इसके बदले में उन्हें इसकी कीमत 18,500 रुपए वापस कर दी जाएगी।

उत्तराखंड के चमोली में बादल फटा, जान माल का भारी नुकसान

नयी दिल्ली, 23 अगस्ता। उत्तराखंड के चमोली जिले के थराली में शुक्रवार देर रात बादल फटने की घटना में सगवाडा तोक के काफलतोली, थराली बाजार, कोटदीप और तहसील थराली परिसर में बारिश का पानी और मलबा घुसने से काफी नुकसान हो गया है और मलब में दबकर लड़की की मौत हो गयी तथा अन्य एक बजुरंग अभी भी लापता है। इस प्राकृतिक आपदा की वजह से पूरे इलाके में तबाही मच गयी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बादल फटने की घटना से थराली बाजार, कोटदीप, और तहसील थराली परिसर में भारी नुकसान हुआ है। तहसील परिसर में उपजिलाधिकारी का आवास और आसपास के कई घरों में भारी मात्रा में मलबा जमा हो गया। तहसील परिसर, रामलीला मैदान, कोट डीप, चेपड़ो सड़क पर खड़ी

■ मलबे में दबने से एक लड़की की मौत हो गई तथा एक बुजुर्ग लापता है।

कुछ गाड़ियां भी मलबे में दब गये हैं तेज बहाव और मलबे के कारण कस्बे की सड़कें टूट गयी हैं।

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार थराली में देर रात 12 बजकर 48 मिनट पर टुनरी गंदेरे में पानी बढ़ ने के कारण तहसील परिसर एवं चेपड़ो बाजार, कोटदीप बाजार एवं कुछ घरों में मलबा घुस गया। कुछ वाहन भी मलबे में दब गये हैं। राजस्व उपनिरीक्षक, थराली द्वारा बताया गया है कि ग्राम सगवाडा में एक मकान में मलबा आने के कारण एक लड़की की मलबे में दबने से मौत हो गयी और एक अन्य बजुरंग लापता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जनपद के जनप्रतिनिधियों से टेलीफोन पर वार्ता कर बादल फटने से हुए नुकसान की विस्तृत जानकारी ली।

कोटा संभाग शनिवार को भी बाढ़ ग्रस्त रहा

सेना , एसडीआरएफ व एनडीआरएफ ने 200 से अधिक लोगों को रैस्क्यू किया



कोटा संभाग में लगातार वर्षा होने से कोटा, बूंदी और बारां के कई इलाके बाढ़ग्रस्त हो गए। सेना, एसडीआरएफ व एनडीआरएफ ने 200 से ज्यादा लोगों का रैस्क्यू करने के लिए नौकाओं का इस्तेमाल किया।

■ बूंदी जिले के नैनवां व देई कस्बे के पास के गांव जलमग्न हो गये। कोटा जिले में दीगोद के निमोद हरिजी गांव व आसपास के इलाके में आज भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं।

कोटा, 23 अगस्त (निसं)। कोटा संभाग में वर्षा का क्रम शनिवार दोपहर तक जारी रहा। कोटा, बूंदी और बारां के कई इलाके बाढ़ ग्रस्त हो गए हैं। जहां पर 8 से 10 फीट पानी भर गया है। लगातार बारिश होने से पानी लगातार बढ़ रहा है।

संभाग में करीब एक दर्जन कच्चे मकान गिर गए हैं। तीन दर्जन के आसपास कच्चे-पक्के मकान में क्षतिग्रस्त हैं। इनमें बारां, बूंदी व और कोटा के मकान शामिल हैं। सेना, एसडीआरएफ व एनडीआरएफ ने यहां पर 200 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है। पूरी रात इन इलाकों में सेना ने ऑपरेशन चलाया है। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए नौकाओं का इस्तेमाल किया गया है।

इधर बूंदी जिले में जलप्रलय जैसे हालात हैं। नवलजगार और जैतसागर झीलें उफान पर हैं। झीलें से छोड़े गए हजारों ब्यूस्के पानी ने शहर और गांवों में बाढ़ आ गई है।महावीर कॉलोनी, मजिस्ट्रेट कॉलोनी और देवपुरा जैसे इलाकों में घरों में भारी बारिश से नैनवां और देई कस्बे के आसपास के गांव जलमग्न हो गए। कलेक्टर अश्वय गोदारा, एसपी राजेंद्र कुमार मीणा खुद मौके पर डटे हैं, वहीं, सेना, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टोमें लगातार राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। लाखेरी पुलिस उपाधीक्षक नरेंद्र नागर ने बताया कि कस्बे की लालपुलिया और शिवनगर बस्तियों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए अभियान चलाया गया।

बूंदी पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि सेना के साथ एसडीआरएफ लगातार रेस्क्यू चलाकर बाढ़ और जलभराव वाले इलाकों से

लोगों को निकाल रही है। कई कस्बों और गांवों का मुख्यालय से संपर्क टूटा हुआ है। सेना, एसडीआरएफ लोगों को बचाने में जुटे हुए हैं।

दूसरी तरफ कोटा जिले के दीगोद के निमोद हरिजी गांव और आसपास के इलाके में आज भी बाढ़ जैसे हालात बने हैं। एसडीआरएफ के इंचार्ज अम्बी लाल ने बताया कि उन्होंने शुक्रवार सुबह से ही ऑपरेशन चलाया हुआ था। उनकी टीम सुल्तानपुर, कैथून, दीगोद, बूंदी के कारेन सहित अलग-अलग गांव में तैनात हैं। लगातार बारिश भी हो रही है इसके चलते पानी नहीं उतर रहा है। दीगोद और सुल्तानपुर में अभी भी हालात बिगड़े हुए हैं।

रास्ते बंद होने के चलते 100 से ज्यादा गांवों से का संपर्क टूट गया है। कहीं नदी नाले के उफान ने राह रोकी है तो कहीं बारिश में पुलिया या अन्य स्ट्रक्चर क्षतिग्रस्त हो गया है। कोटा जिले में कोटा श्योपुर का रास्ता बंद है। इससे सुल्तानपुर, दीगोद, इटावा, खातोली और अन्य जगह का सीधा संपर्क कोटा से टूटा हुआ है। इसी तरह से कोटा कैथून मार्ग बंद है जिसके चलते सांगोद का रास्ता भी बंद हो गया।

बारां जिले की बात की जाए तो यहां भी कई रास्ते बंद हैं। बारां जिले में

एन.डी.ए. के...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) महासचिव ने कहा कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों की अपराध के आधार पर हटाने वाले ये बिल गलत तरीके से बनाए गए हैं और इनका असली निशाना विपक्ष के मुख्यमंत्री और नेता हैं।

आचार्य ने कहा कि संविधान में पहले से ही जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई के पर्याप्त प्रावधान मौजूद हैं। भ्रष्ट नेता को दंड मिलना चाहिए, लेकिन इस बिल से राजनीतिक प्रतिशोध का खतरा बढ़े गा और अस्थिरता पैदा होगी।

आचार्य ने चेतावनी दी कि "ऊपरी तौर पर यह सही लगता है कि भ्रष्ट नेता सत्ता में न रहें, लेकिन असलियत इतनी आसान नहीं है।

ऐसे कानून से राजनीतिक अराजकता और अस्थिरता फैल सकती है।"

अपने सबसे विश्वास...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) दर्शाता है।

गौर की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब भारत और अमेरिका के संबंधों में सहयोग और तनाव दोनों मौजूद हैं। रक्षा सहयोग और इंडो-पैसिफिक रणनीति पर दोनों देश करीब आए हैं, लेकिन शुल्क, ऊर्जा आपूर्ति और रूस तथा ईरान के साथ भारत के आर्थिक संबंधों को लेकर मतभेद बढ़े हुए हैं। ऐसे में राजदूत की भूमिका इन जटिलताओं को संभालने में अहम होगी।

सीनेट की पुष्टि की प्रक्रिया यह तय करेगी कि गौर नई दिल्ली में अपना पद कब तक संभाल पाएंगे। हालांकि उनकी टुप से नजदीकी और राजनयिक अनुभव की कमी के चलते यह नामांकन काफी ध्यान आकर्षित कर सकता है, लेकिन समर्थकों का मानना है कि उनकी संगठन क्षमता और राष्ट्रपति से सीधा संबंध उन्हें अमेरिकी नीतियों को आगे बढ़ाने में एक बड़ी ताकत प्रदान करेगा।

भारत ने इस नामांकन पर औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन नई दिल्ली आमतौर पर उन अमेरिकी राजदूतों का स्वागत करता रहा है जिन्हें राष्ट्रपति का पूर्ण समर्थन प्राप्त हो, क्योंकि इससे संदेश सीधा उच्च स्तर पर पहुंचता है। विश्लेषकों का मानना है कि टुप के करीबी होने के कारण, यदि गौर की नियुक्ति होती है तो उन्हें वाशिंगटन में असाधारण प्रभाव प्राप्त हो सकता है। इस नियुक्ति के माध्यम से टुप ने यह संकेत दिया है कि वे भारत-अमेरिका संबंधों पर व्यक्तिगत रूप से नजर बनाए रखना चाहते हैं। नई दिल्ली के लिए, वाइट हाउस से सीधा संपर्क रखने वाले एक नए दूत का आना नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है, विशेषकर तब जब दोनों देश सहयोग और प्रतिस्पर्धा के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

गौर की नियुक्ति को कई लोग एक सकारात्मक बदलाव के रूप में देख रहे हैं, विशेष रूप से टुप के साथ उनकी गहरी व्यक्तिगत निकटता के कारण। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में जेम्स गोर की मीडिया में शायद सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जिनके बारे में अपने कमी नहीं सुना और मार-आ-लागो के मेयर के

करीब 40 से ज्यादा गांव का संपर्क टूटा हुआ है।

पीपल्स विधायक चेतन पटेल कोलाना का कहना है कि भीषण बारिश हो रही है पर ग्रामीण अपने घरों को छोड़कर नहीं जाना चाहते जबकि पानी काफी है। सभी को अपील कर रहे हैं कि वह घर को छोड़कर और गांव को छोड़कर बाहर आ जाए क्योंकि घर गिर जाएगा तो मुआवजा बाद में लिया जा सकता है। हालांकि लोग घरों में जानवर होने के चलते उन्हें छोड़कर भी नहीं आना चाहते हैं।

खेत पूरी तरह से तालाब बन गए हैं। व्यापारियों को भी काफी नुकसान हो रहा है। बारिश के चलते उनके दुकान मकान में पानी प्रवेश कर गया था जिससे काफी माल खराब हुआ। खेतों में पानी भर जाने के चलते किसानों को नुकसान की भी हो रही है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक अतीश कुमार शर्मा का कहना है कि खेत में चावल की फसल में पानी भर जाने से नुकसान नहीं होगा लेकिन दूसरी फसलों में पानी ज्यादा समय तक भरा रहने से नुकसान की आशंका है।

भारी बारिश के कारण पीडब्ल्यूडी, अन्य एजेंसियों की सड़कों और पुलियों के साथ-साथ अन्य स्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा है। कोटा संभाग में सैकड़ों किलोमीटर सड़कें खराब हो गई हैं। अब इन्हें अस्थायी दुरुस्त कर चलने लायक बनाया जाएगा। साथ ही स्थाई मरम्मत की भी आवश्यकता रहेगी। पीडब्ल्यूडी कोटा के अधीक्षक अभियंता जगदीश गुप्ता का कहना है कि पहले एक बार असेसमेंट करवाया था, जिसमें कोटा जिले में 1025 किलोमीटर की सड़कों को मरम्मत की जरूरत थी। अब इसमें और बढ़ोतरी होगी।

रूप में बताया गया है। उन्हें टुप के अंतरिक मंडल का एक केंद्रीय व्यक्ति माना जाता है। वे इतने प्रभावशाली हैं कि एनान मस्क ने टुप के साथ अपने मतभेद के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया था।

लेकिन कई रणनीतिक विशेषज्ञ गौर की नियुक्ति से चिंतित हैं। उनकी चिंता क्या है? दोहरी भूमिका को लेकर है। भारत के लिए अमेरिकी राजदूत के रूप में वे एक साथ दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत के रूप में भी कार्य करेंगे, जिससे वे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और अन्य देशों में अमेरिकी कूटनीति की जिम्मेदारी उठाएंगे।

भारत के पूर्व विदेश सचिव केंवल सिम्बल ने इस कदम की तीखी आलोचना की है। केंवल सिम्बल ने एक्स पर लिखा, “यह पहली बार है जब भारत में कोई अमेरिकी राजदूत दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत भी है। इसका मतलब है कि उसके पास अमेरिकी विदेश विभाग के साथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स ब्यूरो के अधिकार क्षेत्र को कवर करने वाला एक व्यापक अधिकार होगा। इसका सीधा अर्थ यह है कि वह इस क्षेत्र में भारत के संबंधों पाकिस्तान और हमारे अन्य पड़ोसियों के साथ, निगरानी करेगा। इसका मतलब यह भी है कि वह इस क्षेत्र में अन्य अमेरिकी राजदूतों के साथ परामर्श और समन्वय करेगा, ताकि एक अधिक एकीकृत दृष्टिकोण विकसित किया जा सके।"

मोदी के खिलाफ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव ने अग्रदूट टिप्पणी की। पुलिस उपाधीक्षक रक्षपाल सिंह ने जानकारी देते हुये बताया कि जिलाध्यक्ष हरिश्चंद्र रावत ने बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ कोतवाली तालवेठ में तहरीर दी है, जिस पर आर.जे.डी. नेता व बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ कोतवाली में धारा 173 बी.एन.एस.एस. के तहत एक.आई. आर. दर्ज की गई है व मामले की जांच की जा रही है।